

# पांच साल और 15 घोटाले



## 1. नोटबंदी घोटाला

नोटबंदी करके नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटाला पुरुष बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के पीछे तर्क दिया कि इससे कालेधन पर रोक लगेगी। बहरहाल नोटबंदी से इतना जरूर हुआ कि करोड़ों लोगों की नौकरी छिन गई, सैकड़ों लोगों की जान लाइन में लगे लगे निकल गई। नरेंद्र मोदी का नोटबंदी घोटाला इतना बड़ा है कि इसने सीधे सीधे भारत की जीडीपी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नोटबंदी से जीडीपी को सवा दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसे लेकर दुनिया के 108 अर्थशास्त्रियों ने पर्चा भी लिखा, जिसे नरेंद्र मोदी के प्रख्यात अर्थशास्त्री अरुण जेटली ने कहा कि वे अर्थशास्त्री ही फर्जी हैं। नोटबंदी का घोटाला ऐसे समझा जा सकता है कि इसके जरिए नरेंद्र मोदी ने हमसे आपसे वो सारे पैसे जमा करा लिए जो हमने बड़ी मुश्किलों से कमा रखे थे और उसे लेकर रिलायंस और अडानी से लेकर नीरव मोदी और नितिन संदेसरा तक को बांट दिए। इन सभी लोगों को नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक अलग अलग एकाउंट में दे दिए हैं।

**2. राफेल घोटाला**  
राफेल घोटाला भारत के रक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। डिफेंस में इतना बड़ा घोटाला भारतीय इतिहास में कहीं नहीं मिलता। यह घोटाला करके नरेंद्र मोदी वाकई इतिहास पुरुष बन चुके हैं। राफेल घोटाले में सबसे पहला आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी को सबसे तरीके से ठेका दिलवाया। 31 हजार करोड़ रुपये का यह ठेका असल में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलना था, जिसे लड़ाकू हवाई जहाज बनाने का पुराना एक्सपीरियंस है और यह कंपनी देश की सबसे सम्मानित सरकारी कंपनियों में से एक है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने खुद राफेल वालों से बोलकर यह ठेका अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिलाया। इसके अलावा राफेल डील में कुल 126 लड़ाकू हवाई जहाज मिलने थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने घटाकर 36 कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अवैध तरीके से दबाव डाला। लेकिन इसके बाद द हिंदू समाचार पत्र ने एक के बाद एक करके मामले की कलाई खोलकर रख दी तो सरकार ने कहा कि कागजात चोरी हो गए हैं और वो चोरी द हिंदू अखबार ने की है।

## 3. किसान फसल बीमा योजना घोटाला

नरेंद्र मोदी ने किसानों की फसल का बीमा करने के नाम पर राफेल से भी बड़ा घोटाला किया है, लेकिन चूँकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए शहरी लोगों का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। किसान फसल बीमा योजना में अकेले रिलायंस ने महाराष्ट्र से कुल 173 करोड़ रुपये लिए लेकिन किसानों को सिर्फ 30 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस तरह से अकेले रिलायंस को महाराष्ट्र से 143 करोड़ रुपये का मुनाफा नरेंद्र मोदी ने कमवाया। इसमें से किसानों ने रिलायंस को 19 दशमलव 2 करोड़ रुपये दिए थे और केंद्र और राज्य सरकार ने हमारे पैसे से 77-77 करोड़ रुपये दिए थे। ये हमारे ही पैसे हैं क्योंकि सरकार के पास पैसे के पेड़ नहीं होते। बीमा योजना के नाम पर बीमा कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने 65 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा दे दिए हैं और ये सारी रकम कागजों पर दर्ज है।

## 4. टेलीकॉम घोटाला

नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत का टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से बैट चुका है। कारण- एक खास पूंजीपति को पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर सौंपने की नरेंद्र मोदी ने साजिश की है। टेलीकॉम घोटाले पर नंबर एक पर तो रिलायंस वाला मामला है ही, लेकिन सबसे पहले हमारे अपने बीएसएनएल की बात। बीएसएनएल इम्प्लाइज यूनिनियन का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएनएल को बेचने की साजिश रच रही है और इसी के चलते लगातार बीएसएनएल को कमजोर किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि फोर जी कनेक्शन, जिससे कि आप भी अभी अपना इंटरनेट चला रहे हैं, उसे बेचने का लाइसेंस मोदी जी ने बीएसएनएल को दिया ही नहीं। फोर जी कनेक्शन का सबसे बड़ा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया, फिर एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों को दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे देश भर में बीएसएनएल के कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर भी बैठे कि बीएसएनएल को फोर जी का लाइसेंस दिया जाए, फिर भी नरेंद्र मोदी के कान में जू तक नहीं रेंगी।

बीएसएनएल को नुकसान पहुंचाते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष तौर पर रिलायंस को 4800 करोड़ रुपये का एम्पायर खड़ा करने दिया, जो कि सीधे सीधे इस सरकारी कंपनी का हो सकता था। अभी मुकेश अंबानी जियो के से हर तीसरे महीने पांच सौ से सात सौ करोड़ रुपये कमा रहे हैं। यानी कि सालाना ढाई हजार करोड़ रुपये से ज्यादा। इस पैसे में सबसे बड़ा हिस्सा बीएसएनएल का ही है जिसका कि पूरे देश में सबसे बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस को तर्कीबन सतर हजार करोड़ रुपये की छूट अलग अलग बहानों से नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है और इसकी वजह से पूरे देश भर का टेलीकॉम सेक्टर बैट चुका है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने छह टेलीकॉम कंपनियों पर अधिकारियों से जुमाना न लगाने को कहा जिसकी वजह से 45 हजार करोड़ रुपये का घोटाला अकेले टेलीकॉम सेक्टर में और भी हुआ।

## 5. पेट्रोलियम और गैस घोटाला

मामला केजी बेसिन का है जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपने यार दोस्तों से साठगांठ करके गुजरात सरकार और बैंकों के 19,576 करोड़ रुपये डुबो दिए। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मांडल के नाम पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया और सरकारी निगम को नुकसान पहुंचाया। मोदी ने 2005 में घोषणा की थी कि जीएसपीसी को केजी बेसिन में 2,20,000 करोड़ रुपये के मूल्य का 20 हजार अरब घन फीट गैस का भंडार मिला है। निष्पक्ष एवं महालेखा परीक्षक यानी कैंग ने काफी दिन तक कैंग को उस केजी बेसिन में अभी तक कोई गैस नहीं मिली, अलबत्ता मोदी जी इस बीच नाला गैस बनाने की तरकीब निकाल लाए। इसी जीएसपीसी से जुड़ा एक और मामला है जिसमें नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि उन्होंने 10651 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के

नाम पर खर्च किए लेकिन ये पैसे उन्होंने कहां खर्च किए हैं, न तो उन्होंने इसका हिसाब दिया और न ही इन पैसे का जिक्र कारपोरेशन के एकाउंट में करने दिया। कैंग ने केजी बेसिन का जो ऑडिट किया, उसके मुताबिक जीएसपीसी 64 'गैस ब्लॉक्स' की मालिक थी।

जीएसपीसी ने इन 64 गैस ब्लॉक्स में से 45 गैस ब्लॉक्स को सरेंडर कर दिया, जिससे 2,992.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह सरेंडर एक खास पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बौर किस्सी टेंडर के जीएसपीसी ने दो 'ज्वाइंट वेंचर पार्टनर' बना लिए थे- 'जियो ग्लोबल रिसोर्सेस' और 'जुविएंट ऑफशोर ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड'। एक अंबानी की कंपनी तो दूसरी बिरला की कंपनी। दोनों कंपनियों को अलग-अलग 10-10 प्रतिशत हिस्सा दिया गया। कमाल की बात यह है कि जियो ग्लोबल रिसोर्सेस को 10 प्रतिशत हिस्सा मुफ्त में दिया गया, जबकि मोदी जी के मुताबिक जीएसपीसी के पास 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गैस भंडार था। इतना ही नहीं, जीएसपीसी ने इन दोनों प्राइवेट कंपनियों की ओर से 2,319.43 करोड़ रुपये का खर्च भी किया, जिसकी एक फूटी कौड़ी भी इन कंपनियों ने सरकार को वापस नहीं दी। 2,319.43 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान सरकारी खजाने को हुआ। जीएसपीसी ने कई ऑयल व गैस ब्लॉक्स में एक और कंपनी गुजरात नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड (जीएनआरएल) से भी ज्वाइंट वेंचर किया। जीएनआरएल उस समय के गुजरात के पेट्रोलियम मंत्री, सोरभ पटेल व उनके परिवार की कंपनी है। मोदी जी की नाक के नीचे उनके मंत्री अपने विभाग की सरकारी कंपनी से ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे। जीएनआरएल का नाम 'पनामा पेपर्स' में नामित दो कंपनियों से जुड़ा है, जिन्हें जीएनआरएल की सॉल्यूशंस बताया जाता है। जीएसपीसी से जुड़े सब अधिकारी भारत सरकार में सर्वोच्च पदों पर आसिन हैं।

जब गुजरात का 20,000 करोड़ जीएसपीसी में डूब रहा था, उसी समय नरेंद्र मोदी ने उर्जित पटेल को जीएसपीसी का 'इंडिपेंडेंट डायरेक्टर' व 'चेयरमैन, ऑडिट कमिटी' नियुक्त कर रखा था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी प्रकार डीजे पांडेयन, जो जीएसपीसी के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, मोदी जी ने उन्हें अक्टूबर, 2014 में गुजरात का चीफ सेक्रेटरी बनाया और फरवरी, 2016 में वे एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। जीएसपीसी के पूर्व एमडी तपन रे भी जून, 2015 में डायरेक्टर जनरल, एनआईसी, अगस्त, 2015 में भारत सरकार के कंपनी सचिव और अक्टूबर, 2015 में सेबी के डायरेक्टर बन गए। जीएसपीसी के 2014 से 2016 तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे अतानू चक्रवर्ती को भी फरवरी, 2016 में मोदी ने भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल, हाईड्रोकार्बन नियुक्त कर दिया। 4 अगस्त, 2017 को वित्तीय तौर से 20,000 करोड़ डुबोने के बाद जीएसपीसी के 80 प्रतिशत शेयर को भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों 'ओएनजीसी' द्वारा 7,738 करोड़ में खरीद लिया गया। हालांकि 2005 से आज तक जीएसपीसी के केजी बेसिन ब्लॉक से कोई गैस नहीं मिल पाई, फिर भी ओएनजीसी ने इसे क्यों खरीदा?

## 6. चावल घोटाला

छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने

भी 36 हजार करोड़ रुपये का चावल घोटाला किया है। धान का कटोरा कहा जाने वाले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और उनके घर वालों ने मिलकर जो घोटाला किया है, वहां के विधानसभा चुनावों में ये एक मेन मुद्दा भी बना। अब इस घोटाले में जांच के आदेश हो चुके हैं। यह घोटाला तब पकड़ में आया जब छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने 12 फरवरी 2015 को राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापे मार कर करोड़ों रुपये बरामद किये थे। आरोप है कि इस छत्तीसगढ़ के छत्तीस हजार करोड़ी इस चावल घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपियों से एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें 'सोएम मैडम' समेत तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के कई परिजनों के नाम कथित रूप से रिश्तत पाने वालों के तौर पर दर्ज थे।

आरोप है कि इस कथित डायरी के 107 पन्नों में विस्तार से सारा कथित लेन-देन दर्ज था लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने इस डायरी के केवल 6 पन्नों का सुविधानुसार उपयोग किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के तत्कालीन मुखिया मुकेश गुप्ता ने सर्वजनिक तौर पर इस मामले को लेकर स्वीकार किया था कि इस घोटाले के तार जहां तक पहुंचे हैं, वहां जांच कर पाना उनके लिये संभव नहीं है। आरोप है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में राइस मिलरों से लाखों किंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपये की रिश्ततखोरी की गई। इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी घोटाला किया गया। इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

## 7. एनपीए घोटाला

अपने चाहने वालों को लोन देकर नरेंद्र मोदी ने पांच लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का एनपीए घोटाला किया है। यह किसी और की नहीं बल्कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 30 जून 2014 से लेकर दिसंबर 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए बढ़कर सीधे सीधे तीन गुना हो चुका है। रिजर्व बैंक ने बताया कि 30 जून 2014 तक कुल एनपीए 2 लाख 24 हजार 542 करोड़ रुपये था और जिस नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2017 तक बढ़ाकर 7 लाख 23 हजार 513 करोड़ रुपये कर दिया। इतने बड़े पैसे कहां गए, इसका कुछ कुछ पता चला है। बीजेपी के कई नेताओं के रिश्तेदार और जानने वाले पनामा पेपर्स से लेकर कई और बड़ी चोरियों में पकड़े गए हैं जिनमें उन्होंने भारी मात्रा में पैसे इधर से उधर किए थे। उधर नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अजित डोभाल के दोनों पुत्र ऑलरेडी टेक्स हैवेन में इसी का धंधा कर रहे हैं।

## 8. जय शाह पुत्र अमित शाह का घोटाला

नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के एक साल के अंदर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी का कारोबार 16,000 गुना बढ़ गया। एक साल में जय शाह वलद अमित शाह की कंपनी की इनकम 50,000 रुपये से बढ़कर 80 करोड़ रुपये हो गई। ये बात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनोज (आरओसी) में दाखिल किए गए दस्तावेजों से सामने आईं। इस घोटाले के लिए औने पौने दाम पर सरकार से जमीन भी हासिल की गई। कंपनी की बिलेंस शीटों और आरओसी से हासिल की गई वार्षिक रिपोर्टों से ये बात उजागर होती है कि 2013 और 2014 के मार्च में समाप्त होने

वाले वित्तीय वर्षों में शाह की टेंपल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई खास उल्लेखनीय कारोबार नहीं कर रही थी और इन वर्षों में कंपनी को क्रमशः 6,230 और 1,724 रुपये का घाटा हुआ। 2014-15 में कंपनी ने महज 50,000 के राजस्व पर 18,728 रुपये का लाभ दिखाया। 2015-16 में कंपनी का टर्नओवर आसमान में छलांग लगाते हुए बढ़कर 80.5 करोड़ रुपये को छू गया।

## 9. चिकी घोटाला

महाराष्ट्र सरकार में ग्रामीण और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे को जो पैसा आदिवासी बच्चों के स्कूल के लिए चिकी, कालीन, बर्तन, किताबें, नोटबुक, वॉटर फिल्टर और दूसरे सामान खरीदने के लिए मिला था, उसकी वे चिकी खरीद कर खा गईं। बीजेपी की इस फायरब्रांड नेता पर आरोप है कि इसने बच्चों के लिए जो सामान खरीदने थे, उसमें 206 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पंकजा मुंडे ने यह घोटाला ठेका नियमों को नजरअंदाज करके किया। आरोप है कि पंकजा मुंडे के डिपार्टमेंट ने कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ही दिन 13 फरवरी को 24 सरकारी आदेश जारी कर दिए।

जबकि महाराष्ट्र सरकार का नियम है कि 3 लाख रुपए से अधिक कीमत के हर सामान को खरीदी सिर्फ ई-टेंडर के जरिए होनी चाहिए। लेकिन नवी मुंबई की जगतगुरु कंपनी, नासिक की एक्वेस्ट कंपनी, सिंधु दुर्ग जिले की सूर्यकांता सहकारी महिला संस्था, साई हाईटेक और नीतिराज इंजीनियर्स को करोड़ों का काम बिना ई-टेंडर के दिए जाने की बात सामने आई और उसकी खरीद में गडबडी भी पाई गई। पंकजा मुंडे के ऊपर ये भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पसंद की कंपनियों से बच्चों के खाने का सामान खरीदा। जो खरीदारी हुई उसका कोई टेंडर भी नहीं भरा गया था।

## 10. हेमा मालिनी जमीन घोटाला

नरेंद्र मोदी की बीजेपी से ही सांसद रहीं हेमा मालिनी पर भी जमीन के मामले में घोटाला करने के आरोप लगे हैं। हेमा मालिनी को उनके डॉस स्कूल के लिए करोड़ों रुपये की कीमती सरकारी जमीन महज 70 हजार रुपये में दी गई। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी का सांसद हैं और उन्हें महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने अंधेरी-ओशिवरा जैसे महंगे इलाके में सिर्फ 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2000 वर्ग मीटर जमीन नाट्यविहार कला केंद्र के नाम से बनने वाले डॉस स्कूल के लिए आवंटित की है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को उनके डॉस स्कूल के लिए करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन महज 70 हजार रुपये में देने के बाद मचे बवाल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 1984 के उस गवर्नमेंट रेजॉल्यूशन (जीआर) को रद्द कर दिया है जिसके तहत हेमा मालिनी सहित कई लोगों को सस्ते दर पर जमीन मुहैया कराई गई थी। ऐसा होने के बाद अब किसी

## 15. स्मृति ईरानी सांसद निधि घोटाला

स्मृति ईरानी पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा की सांसद और केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया। उनका भ्रष्टाचार सबसे पहले गुजरात के एक आईएमएस ने पकड़ा। फिर कैंग ने भी इस घोटाले को पकड़ा और पिछले साल यानी कि 2018 में कैंग ने अपनी रिपोर्ट नंबर चार में स्मृति ईरानी के काले कारनामे उजागर किए। कैंग के मुताबिक, बिना किसी निविदा प्रक्रिया के एमपीएलएडी फंड यानी सांसद निधि से करीब 6 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें 84,53,000 का फर्जी भुगतान शामिल है। दरअसल स्मृति ईरानी ने सांसद बनने के बाद गुजरात के आणंद जिले के माणसोल गांव गोद लिया था। स्मृति ईरानी ने फोन करके 'शारदा मजदूर कामदार सहकारी मंडली' नामक सहकारी संस्था को क्रियान्वयन का कान्ट्रैक्ट दिलवाया। बहरहाल, स्मृति ईरानी के इस घोटाले पर गुजरात हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस ए एस देवे और जस्टिस बरिन वैष्णव की पीठ ने मामले में सरकार की ओर से अब तक की गई जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी है।

को सस्ते में जमीन नहीं मिल पाएगी।

## 11. नीरव मोदी घोटाला

2011 से नीरव मोदी को पीएनबी से बिना किसी गारंटी के गैरकानूनी तरीके से बिना बैंक के सॉफ्टवेयर में एंटी किए लेटर ऑफ अंटरटेकिंग (एलओयू) जारी होते गए और जनवरी 2016 तक यह बात पीएनबी के किसी भी अधिकारी या आरबीआई की जानकारी में नहीं आई। हर साल बैंकों में होने वाले ऑडिट और उसके बाद जारी होने वाली ऑडिट रिपोर्ट भी इस फर्जीवाड़े को नहीं पकड़ पाई। बात एक या दो एलओयू की नहीं बल्कि 150 एलओयू जारी होने की है। नीरव मोदी के साथ साथ कई और कारोबारियों ने इसी तरह से घोटाला किया जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी और देवेन्द्र फडनवीस ने उनकी मदद की।

इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। जनवरी 2018 में यह घोटाला सामने आया और मोदी जी ने छोटे मोदी यानी नीरव मोदी को आराम से देश छोड़कर जाने दिया। मामला सिर्फ नीरव मोदी का ही नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी समेत 31 कारोबारियों को हमारा पैसा लेकर विदेश भागने दिया है। इनमें प्रमुख हैं- आशीष जोबनपुत्र, पुष्पेश कुमार वैद्य, संजय कालरा, वर्षा कालरा, और आरती कालरा, सोमित जेना, विजय कुमार रेवा भाई पटेल, सुनील रमेश रूपाणी, पुष्पेश कुमार वैद्य, सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, हरसाहिब सिंह, हरलीन कोर, अशीष जोबनपुत्र, जतीन मेहता, नीरव मोदी, नीशल मोदी, अमी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, चेतन जयंतिलाल संदेशरा, दीपि चेतन संदेशरा, नितिन जयंतिलाल संदेशरा, सभ्य सेठ, नीलेश पारिख, उमेश पारिख, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, हेमंत गांधी, ईश्वर भाई भट, एमजी चंद्रशेखर, चेरिया वी. सुधीर, नोशा कादोजि और चेरिया वी. सादिक।

## 12. व्यापम घोटाला

एसआईटी के आंकड़े बताते हैं कि व्यापम घोटाले में अब तक 40 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं तो कांग्रेस का कहना है कि अब तक कुल 46 लोग इस घोटाले में मारे गए हैं। मारे गए लोगों में पत्रकार अक्षय सिंह भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले का रहस्य गहरता जा रहा है। घोटाले को उजागर करनेवाले गवाहों और आरोपियों की संदिग्ध हालात में एक के बाद एक मौत हो रही है। ये घोटाला 2013 में तब सामने आया, जब आरोप लगे कि प्री मेडिकल टेस्ट - पीएमटी की मेरिट लिस्ट में 300 से ज्यादा फर्जी उम्मीदवारों के नाम हैं। बाद में घोटाले की जब परतें खुलीं तो पता चला कि सिर्फ मेडिकल एडमिशन ही नहीं, शिक्षकों से लेकर कई सरकारी नौकरियों में बहाली का भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। शुरूआती जांच के बाद इस घोटाले से जुड़े कई बड़े नाम सामने आए, जिनमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बीजेपी के लक्ष्मीकांत शर्मा, घोटाले का सूत्रधार डॉक्टर जगदीश सागर और राज्य में पीएमटी एक्जाम इंचार्ज सी के मिश्रा शामिल हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अभी तक करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार किया है।

## 13. अडानी पॉवर घोटाला

कोयला और बिजली उपकरण में ओवर प्राइसिंग के जरिए अडानी समूह ने 50 हजार करोड़ का घोटाला किया है। डीआरआई यानी रिजर्व खुफिया निदेशालय की 97 पन्नों की रिपोर्ट में अडानी से जुड़े ग्रुप अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के भी नाम हैं। डीआरआई ने अडानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल चीन और दक्षिण कोरिया से उपकरण सीधे आते हैं, लेकिन जो इनवाइस होते हैं वो संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते आते हैं, जहां बिल में बदलाव करके कीमत ज्यादा दिखाई जाती है। फिर इन उपकरणों की कीमत जनता से अधिक बिजली रेट लगाकर वसूली जाती है। बिजली पर दो रुपया टैक्स प्रति यूनिट अडानी टैक्स के तौर पर लग रहा है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटील्लिजेंस ने कोयला आयात के मामले में भी अडानी का 29 हजार करोड़ रुपये का घोटाला खोज निकाला है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका इस घोटाले की एसआईटी जांच की मांग कर रही है।

## 14. पीयूष गोयल शेर घोटाला

मोदी सरकार के प्रभावशाली मंत्री पीयूष गोयल ने भी घोटाला किया है। पीयूष गोयल ने दस रुपये कीमत के शेर 9,950 रुपये में ऐसी कंपनी को बेचे, जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी रही है। ऐसा तब हुआ जब वह ऊर्जा मंत्री थे। कांग्रेस ने पीयूष गोयल पर आरोप लगाया कि ऊर्जा मंत्री रहते कंपनियों, शेर और अधोषिप्त संपत्ति की जानकारी भी गोयल ने छुपाई और अपने पद का दुरुपयोग किया।